हिन्दी साप्ताहिक

REGI No:- UABIL/25/A3383

उत्तराखण्ड अभ्युदय

♦वर्ष -02 ♦ अंक-29 ♦देहरादून - रविवार 17 मई 2026 ♦पृष्ठ : 4 ♦मूल्यः 1/-15

केरलम के नए मुख्यमंत्री होगे वीडी सतीशन, हाईकमान ने लगाई मुहर

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम । आखिरकार लंबे समय तक ऊहापोह के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने केरल के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस पद के लिए वीडी सतीशन का नाम फाइनल किया है। वो प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी में लोग इसे नई पीढ़ी के औपचारिक आगमन के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह ऐलान दिल्ली में किया, जिसमें प्रमुख रूप से दीपा दासमुंशी, मुकुल वासनिक और अजय माकन शामिल रहें। यह फै. सला, जिसे काफी समय तक टाला गया था, कांग्रेस ने अपने खास नाटकीय अंदाज में घोषित किया।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल अंतिम दौर की चर्चाओं के दौरान दिल्ली में मौजूद थे। नेतृत्व का फैसला बताने से पहले उन्हें राहुल गांधी के साथ बैठक के लिए बुलाया गया।

इस बीच, वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को राहुल गांधी का निजी फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि अब फैसला हो चुका है और सतीशन को मंजूरी मिल गई है।

सतीशन के लिए यह पद उनकी राजनी. तिक यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। यह फैसला केरल में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी और चुनावी हार के बाद कांग्रेस के खुद को नए तरीके से तैयार करने की कोशिश को भी दिखाता है।

कोच्चि जिले में जन्मे सतीशन इस महीने के आखिर में 62 साल के हो जाएंगे। उन्होंने अपनी पहचान गुटबाजी की रा. जनीति से नहीं बल्कि विधानसभा में अच्छे प्रदर्शन और संगठन में लगातार काम करके बनाई है।

पेशे से वकील सतीशन ने 2001 में परावुर से विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उन्हा. ंने कांग्रेस के तेज और प्रभावशाली वक्ताओं में अपनी पहचान बनाई।

आंकड़ों, तीखे व्यंग्य और दमदार बोलने के अंदाज के कारण सतीशन वामपंथी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन गए। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सबसे बड़ी सफलता ऐसे समय में मिली जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी।

2021 के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की बड़ी हार के बाद सतीशन को अच. ानक विपक्ष का नेता चुना गया। शुरुआत में कई लोगों ने उन्हें अंदरूनी खींचतान के बीच एक समझौता उम्मीदवार माना था। सतीशन ने इस जिम्मेदारी को अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने का बड़ा मौका बना लिया।

सोने की तस्करी का मामला हो, एआई कैमरे से जुड़े आरोप हों या कानून-व्यवस्था को लेकर विजयन सरकार पर लगातार हमले सतीशन ने खुद को केरल में वाम. पंथी सरकार के खिलाफ सबसे प्रमुख और आक्रामक नेता के रूप में स्थापित किया।

मुख्यमंत्री ने 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुल

307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिसमें 243 चिकित्सा अधिकारियों, 42 फार्मासिस्ट, उद्यान विभ. ाग के अन्तर्गत 22 प्रयोगशाला सहायकों एवं मशरूम पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल रोजगार का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की सवा करोड़ जनता की सेवा का संकल्प पत्र है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में संकट की घड़ी में जनता की पहली उम्मीद स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्मिक ही होते हैं। उन्होंने नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों से कहा कि वे संवेदनशीलता, समर्पण और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को उपचार का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक 62 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा लगभग 12 लाख मरीजों का 2200 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस उपचार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और संचालन तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि 2 निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही 9 नर्सिंग कॉलेज और 3 नर्सिंग स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण प्रगति पर है। दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन एवं हेली एंबुलेंस सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कीवी, ड्रैगन फ्रूट, हाई डेंसिटी एप्पल, मशरूम उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन जैसी उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव नियुक्त युवा प्रदेश को कृषि नवाचार और आधुनिक उद्यानिकी के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता से हो रही है। प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कान. ून लागू किया गया है। इसका परिणाम है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में 32 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उद्यान विभाग द्वारा अतिसघन सेब बागवानी, कीवी मिशन, ड्रैगन फ्रूट मिशन, मधुमक्खी पालन नीति तथा जाइका परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में उभर सकता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में गुणात्मक सुधार आएगा।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नये चिकित्सकों और फार्मासिस्ट की नियुक्ति होने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों तक चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता हो और लोगों को अपने निकटतम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी चिकित्सक पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ जन सेवा के प्रति समर्पित रहेंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, सचिव सचिन कुर्वे, डॉ. एस. एन. पाण्डेय एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड सहित 19 राज्यों में 29 मई से शुरु होगा SIR

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में 19 राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की घोषणा कर दी है। उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में 29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र के प्रिंटिग,कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बंधी कार्य सम्पादित किए जाएंगे। 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन करेंगे। उत्तराखण्ड में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा। इसी क्रम में 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। इसी बीच 10 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक सभी नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार 15 सितंबर 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में 11733 पोलिंग बूथ के सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश में राजनैतिक दलों द्वारा 21 हजार 808 बीएलए की तैनाती कर दी गई है।

मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्लीगाड सहस्त्रधारा में आपदा प्रभा. वित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपदा से आए मलवे का तत्काल चौनलाइजेशन करने के निर्देश देते हुए कहा कि बरसात से पूर्व संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला प्रशासन के अधि कारियों को खनन संबंधी टेंडर प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए, जिससे मलवा निस्तारण एवं नदी-नालों के सुचारु प्रवाह का कार्य तेजी से किया जा सके।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनहित को प्राथ. मिकता देते हुए प्रभावित क्षेत्रों से जल्द से जल्द मलवा हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी विभ. ागीय अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के भी निर्देश दिए।

एमडीएम पोर्टल की तकनीकी खामी पर भड़का शिक्षक संघ

विकासनगर)। उत्तराखंड राज्य प्राथ. मिक शिक्षक संघ ने मध्याह्न भोजन योजना के पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग तकनीकी खामी का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया, तो आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के पोर्टल पर पिछले दो दिनों से आ रही तकनीकी समस्या को लेकर नाराजगी नाराजगी जताई है। संग. ठन पदाधिकारियों ने कहा कि पोर्टल पर लगातार मैसेज न जाने की समस्या के बावजूद विभाग तकनीकी खामी का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रहा है, जबकि मामूली त्रुटि पर शिक्षकों के वेतन रोकने जैसे आदेश जारी कर दिए जाते हैं। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मधु पटवाल ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ-साथ विद्यालय संचालन एवं अन्य विभागीय दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इसके बावजूद पीएम पोषण योजना के अंतर्गत एमडीएम सूचना प्रेषण में जरा सी त्रुटि होने पर बिना ठोस कारण जाने सीधे वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं।

सम्पादकीय

लोकल की ग्लोबल पहचान

देवभूमि:शुभां वर्धयति ग्राम्यजीवनसमृद्धये।
कुटीरे उद्योगा:स्फुरन्ति, अन्नसंस्कारणं च शोभते।।
पर्यटनं पुष्यति सौख्यहेतुं, जनकल्याणविवृद्धये।
नवोन्मेषप्रेरिता आत्मनिर्भरता प्राप्नुयात्।।

अर्थात

देवभूमि उत्तराखंड अपने ग्राम्य जीवन की समृद्धि बढ़ा रही है,कुटीर उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को चमकाने का प्रयास है।पर्यटन जनकल्याण के लिए उन्नति पा रहा है,नवाचार से प्रेरित होकर यह प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है।

'स्टार्टअप इंडिया', 'वोकल फॉर लोकल', 'मेक इन इंडिया','स्किल इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों से हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। स्थानीय उत्पादों को ई-कामर्स के माध्यम से ग्लोबल मार्केट एवं ग्लोबल पहचान मिल रही है ।

राज्य में स्थापित उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया गया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और डैडम् नीति से राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।निवेश प्रोत्साहन के लिये यूके-स्पाईस नाम से निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित कर निवेशकों को समर्पित "निवेश मित्र" की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

'एक जनपद, दो उत्पाद' योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने का काम किया है। इसके अलावा, 'स्टेट मिलेट मिशन', 'फार्म मशीनरी बैंक', 'एप्पल मिशन', 'नई पर्यटन नीति', 'नई फिल्म नीति', 'होम स्टे','वेड इन उत्तराखंड' 'सौर स्वरोजगार योजना' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं।

"स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार'' के मंत्र को आत्मसात करना है।यदि हम स्थानीय उत्पादों/ वस्तुओं के विपणन को प्राथमिकता देंगे,तो हमारा ये कदम न केवल हमारे कारीगरों,किसानों और उद्यमियों को सशक्त बनाएंगे,बल्कि आत्मनिर्भरता की सशक्त संकल्पना को भी सुदृढ़ता प्रदान करेंगे।

जय देवभूमि उत्तराखंड!! जय भारत!!

डॉ गार्गी मिश्रा

जापान की राजनीति में एक भारतीय योगी

अरुण नैथानी

कोई व्यक्ति भारत से स्कॉलरशिप लेकर जापान पढ़ने जाये। फिर भारत से लौटने के बाद जापान में सम्मानजनक नौकरी हासिल कर ले। इसके बाद जापानी समाज में इतनी पैठ बना ले कि चुनाव जीतने में कामयाब हो जाये तो निश्चित ही उसकी मेहनत और सामाजिक सरोकारों को श्रेय देना होगा।

भारतीय मूल के योगेंद्र पुराणिक, जिन्हें योगी के नाम से जाना जाता है, पिछले दिनों जापानी मीडिया में छाये हुए थे। उन्होंने पहले ऐसे भारतीय होने का गौरव हासिल किया, जिसने जापान में कोई चुनाव जीता हो। असेंबली चुनाव में उन्होंने भारतीय बहुल उस इलाके में कामयाबी हासिल की जहां बड़ी संख्या में चीनी व कोरियाई नागरिक रहते हैं। जिनके बूते वे वार्ड असेंबली का चुनाव जीतने में कामयाब रहे।

दरअसल, योगी एक पढ़ने-लिखने वाले व्यक्ति रहे हैं। उन्हें राजनीतिक जीवन में सक्रियता का सबक तब मिला जब जापान में 2011 में भूकंप सुनामी आई। जापानी समाज के उदात्त मूल्यों व सेवा के सरोकारों ने उन्हें गहरे तक प्रभावित किया। उन्होंने समाज सेवा में बढ़-चढ़कर भागीदारी की और मन ही मन निर्णय किया कि वे अब जापान के ही होकर रहेंगे।

भारत में हो रहे आम चुनावों की खबरों से योगी बेखबर नहीं हैं। वे बताते हैं कि जापानी राजनीतिक जीवन में भारतीय राजनीतिक जीवन से कोई साम्य नहीं है। वहां हर उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार पर अनावश्यक आक्षेप नहीं करता बल्कि उसका पूरा सम्मान करता है। चुनाव बेहद व्यवस्थित ढंग से होते हैं। नियमों के अनुपालन के लिये सुरक्षा व्यवस्था की पैनी निगाह होती है। साथ ही जापानी चुनाव प्रचार के दौरान घर-घर दस्तक देने और व्यक्तिगत मुलाकातों से खासा परहेज करते हैं। साथ ही चुनाव लड़ने के तौर-तरीकों के लिये उम्मीदवार को प्रशिक्षित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीयता के उच्च मूल्यों का अनुपालन करने वाले जापानी समाज में चुनावी खर्च के विवरण में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाती है। योगी भारत में आकर राजनीति करने के मुद्दे पर हाथ खड़े कर देते हैं। योगेंद्र बताते हैं कि भारतीय राजनीति में पारदर्शिता की कमी महसूस होती है। यदि बदलाव के प्रयास होते भी हैं तो वे फलीभूत होते नजर नहीं आते। वे देश में चुनाव सुधारों की बड़ी पहल की आवश्यकता महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के लिये मैं राजनीति में आया हूं। मकसद राजनीतिक महत्वकांक्षा नहीं, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन है। हां, योगेंद्र एक बात जरूर स्वीकारते हैं कि जापान में भी भारत की तरह वंशवाद नजर आता है। खासकर एलडीपी में, जिसकी इस देश में काफी पकड़ है। वे मानते हैं कि पार्श्व में धार्मिक मान्यताएं जापानी राजनीति में खासी भूमिका निभाती हैं। योगी को जापान की कांस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिला। खासकर उनके मार्गदर्शक और सांसद अकिहीरो हत्सुशीका का उन्हें काफी सहयोग मिला। जिस इलाके में योगेंद्र पुराणिक रहते हैं वहां भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है, जो करीब साढ़े चार हजार के आसपास होगी। हालांकि पूरे जापान में भारतीयों की संख्या 34 हजार के आसपास होगी। बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी यहां रहते हैं। योगी मानते हैं कि जापानी लोग बहुत विनम्र होते हैं और स्वच्छता के प्रति बेहद सजग। राष्ट्रीयता के उच्च मानकों का वे पालन करते हैं। भूकंप व सुनामी की त्रासदी के दौरान योगी को स्थानीय लोगों से जुड़ने का मौका मिला। उन्होंने इस मौके को जापानियों के दिलों में जगह बनाने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने तब जापान की नागरिकता ली और राजनीति में उतरने का मन बनाया। इस तरह जापान के चुनाव में जीत हासिल करने वाले वे पहले भारतीय बने। जापानी मीडिया ने भी इस खबर को हाथों-हाथ लिया।

योगी बताते हैं कि वह इस जीत के जरिये जापानियों और विदेशी मूल के लोगों के मध्य एक सेतु का काम करेंगे। साथ ही क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयां देकर कालांतर संसद का चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। जापान में नई पहचान बनाने वाले इस भारतवंशी को वाम रुझान वाली पार्टी का समर्थन हासिल हुआ है, लेकिन वे सभी विचारधाराओं वाले लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। उनका विकास का अपना एजेंडा है और वे बदलाव के वाहक बनना चाहते हैं। वे मानते हैं कि सामाजिक बदलाव के कई लक्ष्य बिना राजनीति में आये पूरे करने संभव नहीं थे, इसीलिये राजनीति में आने का मन बनाया। यह कोई पेशेवर राजनीति नहीं है, बल्कि सेवा के कार्य में राजनीति को महज माध्यम बनाया गया है। उन्हें विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का सहयोग भी इस जीत में मिला है।

योगी जापान में भारतीय समुदाय द्वारा चलाए जा रहे लिटिल इंडिया कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। उनका मानना है कि वे व्यावहारिक नीतियों से इसके लक्ष्यों का पुनर्निधारण करेंगे, जिससे प्रवासी भारतीयों की जापानी समाज में भागीदारी बढ़े और हम जापानी समाज के करीब आ सकें।

पेशेवर प्रतिभाओं के आने से जगी उम्मीद

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में देश में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा चयनित नौ विभिन्न असाधारण योग्यता वाले अनुभवी पेशेवर विशेषज्ञों को केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्ति दी गई है। देश में पहली बार निजी क्षेत्र से पेशेवर योग्यताओं के चलते नियुक्ति पाने वाले संयुक्त सचिवों को नागर विमानन, कृषि, वित्त, नौवहन के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। इसे लैटरल एंट्री कहा जाता है। अभी इन पदों पर सिविल सर्विसेस से आईएएस बने अधिकारी करीब 25 साल की सेवा के बाद पहुंच पाते हैं। संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल 3 साल का होगा और अच्छा प्रदर्शन होने पर इसे 5 साल तक किया जा सकेगा। इन पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 40 साल रखी गई थी। वेतन और अन्य सुविधाएं केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के समान हैं।

गौरतलब है कि देश में नौकरशाही में लैटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव 2005 में आया था। प्रशासनिक सुधार पर पहली रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की गई थी। तब इसे खारिज कर दिया गया था। 2010 में दूसरी प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गई। 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद 2016 में इसकी संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने इस पर आगे बढ़ने की अनुशंसा की। जुलाई 2017 में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश जारी किया था। तब कहा गया था कि नौकरशाही में लैटरल एंट्री से पेशेवर प्रतिभाओं और मध्यम स्तर के अधिकारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा। कहा गया कि इनके चयन के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा और कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी इनका इंटरव्यू लेगी। सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का अनुभव रखने वाले इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र के पेशेवरों को सरकारी क्षेत्र में लेने के इस नए अभियान का उद्देश्य है कि विभिन्न असाधारण योग्यता वाले अनुभवी पेशेवरों को उनकी प्रतिभा और क्षमता के हिसाब से प्रशासन व देश के विकास में योगदान देने का मौका सुनिश्चित करना है। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को विशिष्ट वेतन-भत्तों के साथ नौकरशाही में सीधे शामिल करने को विभिन्न सरकारों के उन प्रयासों की निरंतरता के साथ देखा जा सकता है, जिसके तहत सरकारें शासन में बाहर से विशेषज्ञता लाना चाहती थीं। सरकारी तंत्र में शुरू हुए निजी क्षेत्र के पेशेवरों के उपयोग के इस अभियान के तहत अपनी सेवाएं देने के लिए देश और विदेश में रहने वाले भारतीय पेशेवरों ने बड़ी संख्या में आवेदन किए थे। बड़ी तादाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, डिजिटल कंटेंट स्क्रिप्ट राइटर्स, एडवर्टाइजिंग पेशेवरों, एकेडमिक विशेषज्ञ, सोशल मीडिया विशेषज्ञ और एप डेवलपर्स जैसे क्षेत्रों से सरकार के साथ काम करने के आवेदन आए थे। आवेदकों में अमेरिका के प्रसिद्ध कोलंबिया, कॉर्नेल और येल जैसे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, एप्पल, गूगल, फेसबुक सहित अन्य प्रमुख वैश्विक कंपनियों में काम करने वाले पेशेवर और साइंटिस्ट भी शामिल थे।

अब निश्चित रूप से अनुभवी कुशल भारतीय पेशेवर प्रशासन का सक्रिय भाग बनकर देश के विकास को गति दे सकते हैं। मोदी सरकार के पहले भी विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा कुछ-कुछ प्रतिभाओं और पेशेवरों को सरकार के कार्यों में सहयोग हेतु जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में नंदन नीलेकणी को लाया गया और उन्हें आधार के लिए अधिकार दिए गए। इंदिरा गांधी भी नियमित रूप से कारोबारी जगत की प्रतिभाओं को बेहतर उपयोग में लाती रहीं। दूरसंचार में क्रांति के लिए राजीव गांधी सैम पित्रोदा को लाए। अटलबिहारी वाजपेयी ने आर. वी. शाही को बिजली सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। जिनके बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वी.पी. सिंह ने अरुण सिंह को जवाबदारी देकर देश के रक्षा संगठन का आधुनिकीकरण करने के कदम उठाए। नरसिम्हा राव भी हरसंभव बेहतरीन प्रतिभाएं जुटाने में सफल हुए। वह मनमोहन सिंह को लाए और उन्हें सीधे वित्तमंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह के वित्त सचिव मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में अब लैटरल एंट्री से देश और विदेश की कुशल प्रतिभाओं और पेशेवरों का प्रशासन तथा सरकारी कार्य में सहयोग लेने का जो अभियान चलाया गया है, वह अवश्य लाभप्रद होगा।

यद्यपि सरकारी तंत्र में निजी क्षेत्र के पेशेवरों और क्षमतावान विशेषज्ञों की संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्तियां लाभप्रद दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। इनमें से प्रमुख चुनौती नियुक्त विशेषज्ञों की गुणवत्ता संबंधी है। पेशेवर विशेषज्ञों को एक खास शैक्षणिक मानक पूरा करना होता है और जिन लोगों को चुना जाता है, उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार से गुजरना होता है। उनके लिए कोई लिखित परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होतीं। चूंकि संयुक्त सचिव पदों पर लैटरल एंट्री पहली बार हुई है, अत: अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति का सर्वश्रेष्ठ तरीका है या नहीं।

दूसरी चुनौती यह है कि शुरुआत से ही विभिन्न संयुक्त सचिवों की नियुक्ति विवादों में आ गई है। ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार इनकी विशेषज्ञताओं का कितना लाभ ले सकती है। जरूरी होगा कि एक खास तरह का माहौल बनाया जाए ताकि विशेषज्ञ काम कर सकें। यह काम आसान नहीं है क्योंकि विशेषज्ञों और आम नौकरशाहों के बीच तनाव अनिवार्य है। इसके अलावा बाहरी लोगों के लिए प्रशासनिक सेवा के नौकरशाहों के साथ मिलकर काम करना आसान नहीं है। जिन लोगों को बाहरी विशेषज्ञ के रूप में चुना जा रहा है, उनके लिए फाइलों और मंत्रियों की बैठक तक पहुंच बनाना भी आसान नहीं है। ऐसे में काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक कार्यपालिका इन बाहरी विशेषज्ञों को किस हद तक काम करने देती है।

हम आशा करें कि एक बार सरकारी तंत्र में लैटरल एंट्री से नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसमें उपयुक्तता पाने पर सरकार नियामकीय प्रमुखों की खोज का दायरा भी बढ़ाएगी। देश के निजी क्षेत्र में प्रतिभाओं की भरमार है।

बच्चों के साथ खुलकर करें सेक्स के बारे में बात

जब 10 साल की प्रिया महादेव ने रात में डिनर के वक्त अपने माता-पिता से जब यह सवाल पूछा कि ऑर्गेज्म क्या है? तो वे दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया अभी इतनी छोटी और उससे इस बारे में बात करना क्या सही होगा? मगर फिर उसके माता-पिता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी बेटी को सेक्स के बारे में इधर-उधर से उल्टी सीधी जानकारी मिले, इससे पहले ही उन्हें अपनी बेटी से इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए।

ऐसे बना बातचीत का जरिया

उसकी मां रुक्मिणी ने बताया, अगले दिन हम लोग साथ में बैठे और उसे समझाया कि सेक्स क्या होता है और यह कैसे काम करता है? इसके फायदे-नुकसान, सही-गलत सबके बारे में बताया। हालांकि अभी वह इतनी छोटी है कि अभी उसे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ सका, लेकिन कम से कम इस बारे में उससे आगे बातचीत करने का कुछ जरिया तो बना।

बच्चों से बात करना हमारी नौतिक जिम्मेदारी

आज रुक्मिणी और उनके पति महादेव के सामने जो स्थिति पैदा हुई, हो सकता है भविष्य में आपका बच्चा भी आपसे ऐसे सवाल करे। इसलिए हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों

को हर चीज की अच्छाई और बुराई के बारे में बताएं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी इस जिम्मेदारी को आसानी से निभा सकते हैं।

जल्द कर दें शुरुआत

साइकॉलजिस्ट मंजुला एमके बताती हैं, आज के जमाने में हर जानकारी खुद ब खुद बच्चों तक पहुंच जाती है। टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि बच्चे समय से पहले ही सब कुछ समझने लगते हैं।

इससे पहले कि वे इन चीजों को गलत ढंग से लें आप उन्हें मेल और फीमेल जेनिटल्ज़ के बारे में खुद ही बता दें।

जब बच्चे हो जाएं 13-14 साल के तो

जब आपका बच्चा 13 सा 14 साल का हो जाता है तो नैचरली ही उनमें विपरीत की तरफ आकर्षित होने वाले हॉर्मोन्स बनने लगते हैं।

ये ही उचित समय है जब आपको उनको सेक्स, प्रेग्नेंसी, एचआईवी जैसी चीजों के बारे में बताना चाहिए। उन्हें कॉन्डम और उसके इस्तेमाल के बारे में भी पता होना चाहिए।

सच्चाई से कराना चाहिए रूबरू

आपको बच्चों को सेक्स के बारे में इस प्रकार बताना चाहिए कि ये केवल फेंटसी न होकर जिंदगी की सच्चाई है। प्यार और सेक्स केवल सपनों की दुनिया में नहीं हकीकत में भी होता है मगर सही पार्टनर के साथ।

बच्चों के सवालों का न करें इंतजार

सेक्स के बारे में आप ये कतई न सोचें कि आपका बच्चा आपसे कुछ पूछेगा तभी आप उसे कुछ बताएंगे, बल्कि आपको स्वयं उसकी गतिविधियों को देखते हुए सही मौका देखकर उससे बातचीत की पहल करनी चाहिए।

इम्यूनिटी बढ़ाने और स्ट्रेस कम करने में मददगार है डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट खाने वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है। हाल ही में हुए एक शोध में यह बात सामने आयी है कि डार्क चॉकलेट, स्ट्रेस यानी तनाव को कम करती है जबकि मूड, याददाश्त और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करने में मदद कर सकती है।

वैज्ञानिकों ने बताया कि कोको, फ्लेव्नॉयड का मुख्य स्रोत है लेकिन यह पहली बार है जब यह जानने का प्रयास किया गया है कि यह मनुष्य के दिमाग, हृदय और रक्तवाहिनी संबंधी तंत्रिका तंत्र को कैसे प्रभावित करता है और कैसे इनके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। फ्लेव्नॉयड एक प्राकृतिक पोषक तत्व है जो फलों, सब्जियों और अनाज में पाया जाता है।

अमेरिका की लोमा लिंडा यूनवर्सिटी के ली एस बर्क ने कहा , सालों तक हमने यह अध्ययन किया कि डार्क चॉकलेट की शुगर की मात्रा का तंत्रिका संबंधी कार्यों पर क्या असर पड़ता है।

अधिक चीनी खाने से हम ज्यादा खुश होते हैं। यह पहली बार था , जब हमने मनुष्यों में एक नियमित आकार के चॉकलेट बार के रूप में कोको की अधिक मात्रा के प्रभाव का आकलन लंबे समय और कम समय के लिए किया और हम इसके नतीजों से बहुत उत्साहित हुए।

बर्क ने दो नए शोध अध्ययनों में प्रमुख जांचकर्ता के रूप में कार्य किया जिसमें पाया गया कि कोको की अधिकता से स्मरण शक्ति, मनोदशा और शरीर की रोग प्रतिरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कोको में पाए जाने वाले फ्लेव्नॉयड्स बेहद शक्तिशाली प्रतिरोधक और सूजन रोधी होते हैं जो दिमाग, हृदय और अन्य अंगों के लिए लाभकारी होते हैं।

घरेलू उपायः कमर के दर्द से पाएं निजात

आप चाहे कितनी भी समझदार मां क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को गोद में उठाने के मामले में आप अकसर कुछ ना कुछ गलतियों तो जरूर करती होंगी। इसका सबसे ज्यादा असर आपकी रीढ की हड्डी पर पडता है और कमर दर्द हो जाता है।

लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि बच्चे को कमर पर लेकर चलना आपकी कमर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। शोधकर्ताओं के द्वारा पता चला है कि कमर दर्द के मरीजों में हर साल लगभग एक करोड मदर्स शामिल होती है। पहले गर्भावस्था, फिर बच्चें को गोद में लेकर चलना और साथ में घर का काम करने से आपको कमर दर्द की समस्या होने की आशंका बढ जाती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने प्यार-दुलार और जिम्मेदारियों से मुंह मोड लें, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है।

ज्यादा झुकें नहीं

हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को गोद में उठाने के लिए ज्यादा झुकने की वजह से भी आपकी कमर में तकलीफ हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप बच्चे को झुककर उठाने की बजाय खडा होना जानता है, तो उसे खडे होकर उठाएं।

हील्स पहनें से बचें

एक या डेढ इंच की ऊंची एडी वाली सैंडल ठीक है, लेकिन इससे जयादा ऊंची एडी की कई मांसपेशियों को छोटा कर सकती हैं।

इससे कमर के निचले हिस्से पर खिचांव पडता है।

बच्चों को हिप्स पर उठाना काफी आरामदायक लगता है, लेकिन लम्बे समय तक ऐसा करने से आप की बॉडी का आकार बिगड सकता है।

इतना ही नहीं, इससे आपकी रीढ को सहारा देने वाली मांसपेशियों पर भी जोर पडता है और वे कमजोर हो जाती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप बच्चे को छाती से चिपकाकर उठाएं और उसकी दोनों टांगें शरीर की दोनों साइड में कर लें।

ज्यादा वजन से बचें

कभी एक साथ ज्यादा वजन उठाने की कोशिश ना करें। बेहतर होगो कि बाजार में खरीदारी करते समय ट्रॉली की बजाय टोकरी में सामान इससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपने कितने वजन का सामान खरीदा है।

साथ ही, एक हाथ में सामान उठाने की बजाय दोनों हाथों में आधा-आधा सामान लें।

ना डालें कमर पर दबाव

ज्यादातर नई माताएं अपने बच्चे को दिन में कम से कम 40 मिनट तो उठाती ही हैं, जबकि दो साल पूरे करते-करते उसी बच्चे का वजन 13- से 18 किलो तक हो जाता है। इसलिए जब आप बच्चे को उठाएं, तो इसके लिए कमर पर दबाव ना डालें। यदि आप सम्भलकर बच्चे को उठाएंगी, तो आप कमर दर्द से बच सकती हैं।

ऐक्सेसाइज करें फिट रहें

अकसर यह देखा गया है कि गर्भावस्था के बाद महिलाओं का पेट वाला हिस्सा लटक जाता है और इसका असर रीढ को सहारा देने वाली मांसपेशियों पर भी पडता है। इसके 2-3 साल में दूसरा बच्चा होने के बाद तो मामला और भी बिगड जाता है। इसलिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, तो हैल्थ को लेकर सजग रहें और नियमित पैदल भ्रमण करें और कसरत भी करें।

स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता की कुंजी: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सचिवालय एथलेटिक्स एंड फिटनेस क्लब की द्विवार्षिक पत्रिका "एक संकल्प : सभी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए" का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्लब द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता, शारीरिक सक्रियता और फिट जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, दोनों ही बेहतर कार्यक्षमता और सकारात्मक जीवन के आधार हैं। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम, दौड़, खेल गतिविधियां और अनुशासित जीवनशैली व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय एथलेटिक्स एंड फिटनेस क्लब द्वारा कर्मचारियों एवं समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए किए जा रहे प्रयास प्रेरणादायी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं, बल्कि सामूहिक सहभागिता, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करती हैं। उन्होंने क्लब के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को भविष्य में भी इसी समर्पण और ऊर्जा के साथ कार्य करते रहने के लिए शुभकामनाएं

दीं।

क्लब की इस द्विवार्षिक पत्रिका में वर्षभर आयोजित विभिन्न गतिविधियों और आयोजनों को शामिल किया गया है। इसमें स्वास्थ्य के लिए दौड़, सचिवालय वार्षिक प्रतियोगिता, अंतर विभागीय प्रतियोगिताएं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ 15 किलोमीटर दौड़, गणतंत्र दिवस पर 26 किलोमीटर दौड़ तथा नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत देहरादून से हरिद्वार तक अखंड रिले दौड़ के माध्यम से गंगा स्वच्छता जनजागरूकता अभियान जैसी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।

इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष ललित चंद्र जोशी, महासचिव राजेंद्र प्रसाद जोशी, पत्रिका संपादक श्रीमती शारदा शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश घींगा, मुख्य सलाहक. ार जीवन सिंह बिष्ट, सलाहकार श्रीमती रीता कौल, उपाध्यक्ष श्रीमती रीना शाही सहित क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

आम लोगों की मेहनत की कमाई लूटने वालों को नहीं बख्शा जायेगा: डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बहुचर्चित एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि गरीब व मेहनतकश जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों की अब खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि चिटफंड योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने वाले घोटालेबाजों पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डॉ. रावत ने कहा कि एलयूसीसी ने पहाड़ के भोले-भाले एवं मेहनतकश लोगों को अनियमित जमा योजनाओं में अधिक लाभ का लालच देकर अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की ठगी की है। उक्त प्रकरण में सीबीआई ने ठोस कार्रवाई करते हुये पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हजारों निवेशकों ने राहत की सांस ली है। डॉ. रावत ने विश्वास जताया कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से जांच कर सभी दोषियों को कानून के तहत कठोर दंड दिलाएंगी।डॉ. रावत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित निवेशकों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में इस प्रकार के चिटफंड घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं । कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ विपक्षी नेता पीड़ित लोगों को गुमराह कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, ।

सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हमारी सरकार की प्रतिबद्धता" : सुबोध उनियाल

देहरादून(। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल द्वारा आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुल 307 चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत नव नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। एक समय भर्ती प्रक्रियाएं नकल एवं भ्रष्टाचार के कारण प्रभावित होती थीं, जिससे योग्य युवाओं का विश्वास व्यवस्था से कमजोर पड़ने लगा था। प्रदेश सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया है, ताकि प्रत्येक परीक्षा एवं नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा 32,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए गए हैं। यह केवल रोजगार नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास, न्याय एवं सुशासन की स्थापना का प्रमाण है।

पूर्व सैनिक परिवारों एवं आश्रितों को शिक्षा, कौशल और रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाना सरकार की जिम्मेदारी: गणेश जोशी

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज आईआरडीटी ऑडिटोरियम,

सर्वे चौक, देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग एवं आईटीडीए के माध्यम से प्रायोजित पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए आयोजित रोजगार मेले में प्रतिभाग किया। यह रोजगार मेला कम्प्यूटर एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चयनित लोगों को नियुक्त पत्र भी वितरित किए और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। रा. जगार मेले में 21 निजी कंपनियों द्वारा प्रतिभ. ाग किया गया है।

इस अवसर पर सै. निक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग एवं आईटीडीए विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह रोजगार मेला केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि वीरभूमि भी है, जहाँ प्रत्येक परिवार देशभक्ति, अनुशासन और त्याग की भावना से जुड़ा हुआ है। मंत्री जोशी ने कहा कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परिवारों एवं आश्रितों को शिक्षा, कौशल और रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनके अंतर्गत शिक्षा अनुदान, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से निरंतर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मंत्री जोशी ने कहा कि पिछले दो वर्षों में सैनिक कल्याण विभाग एवं आईटीडीए विभाग के संयुक्त प्रयासों से 628 पूर्व सैनिक आश्रितों को कम्प्यूटर एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

महा रजिस्ट्रार/जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने की जनगणना कार्य की समीक्षा

देहरादून। भारत के महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने उत्तराखंड में जनगणना कार्य की प्रगति पर संतोष प्रकट किया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को देहराखास इलाके के कुछ घरों में

पहुंचकर जनगणना कार्य की प्रक्रिया को करीब से देखा और फील्ड स्टॉफ से जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित पूरे देश में जनगणना कार्य को लेकर लोग जिस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं, वह उल्लेखनीय है।

जनगणना के कार्य में पहली बार डि. जिटल प्रयोग: मीडिया से बातचीत में महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है, जबकि जनगणना की प्रक्रिया को डिजिटल फार्मेट पर लाया जा रहा है। इससे आंकड़ों की गुणवत्ता बेहतर रहेगी और गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकेगा। उन्होने कहा कि पहली बार स्वगणना का विकल्प दिया गया है। पूरे देश में स्वगणना के विकल्प का इस्तेमाल करने वालों की संख्या का करोड़ में पहुंचना बताता है कि नए प्रयोग को लोग स्वीकार रहे हैं। भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि जनगणना के कार्य में स्वगणना और मजबूत भूमिका निभाएगी।

चुनौतीपूर्ण, लेकिन जल्द नतीजे निकलने की उम्मीद: महा रजिस्ट्रार एवं आयुक्त जनगणना मृत्युंजय कुमार नारायण ने एक सवाल के जवाब में कहा कि डिजिटल माध्यम से जनगणना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद, इस अभियान में सभी लोग उत्साहपूर्वक जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन डाटा एकत्रित करने का विकल्प भी फील्ड स्टॉफ के पास है, लेकिन इसे अनिवार्य रूप से डिजिटल फार्मेट में लाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी कानून-व्यवस्था या फिर तकन. ीकी वजह से जनगणना कार्य में दिक्कत आने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से जनगणना के चलते इसके परिणाम जल्द निकलने की उम्मीद की जा सकती है।

कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छे से समझा रहे हो ना : देहराखास में जनगणना कार्य में व्यस्त सुपरवाइजर भूपेंद्र सिंह बिष्ट और प्रगणक हसीना जैदी से महा रजिस्ट्रार ने पूछा-कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। लोगों को अच्छे से समझा रहे हो कि उनकी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा। फील्ड स्टॉफ ने उन्हें सब कुछ सुचारू ढंग से चलने की जानकारी ही। महा रजिस्ट्रार ने आज देहराखास में जनगणना के कार्य को नजदीक से देखा। स्थानीय निवासी हर्षिता तिवारी और अर्पणा शुक्ला ने कहा कि जनगणना कार्य में सहयोग जरूरी है। यह देश हित का मामला है। जनगणना के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन: महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने देहराखास में जनगणना कार्य निदेशालय के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। अभी तक जनगणना निदेशालय का कार्य मातावाला बाग स्थित किराये के भवन से चल रहा था। इस मौके पर जनगणना कार्य सचिव दीपक कुमार, निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक शैलेंद्र सिंह ने, उपनिदेशक तान्या सेठ, प्रवीण कुमार, आरके बनवारी, सहायक निदेशक संजीव कुमार व अरविंद कुमार सिंह उपस्थित थे।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक **गार्गी मिश्रा** द्वारा इंटर ग्राफिक आफॅसेट प्रिंटर्स 64 नेशविला रोड़ देहरादून, उत्तराखंड से मुद्रित, 98, 2-फ्लोर, सनशाइन अपार्टमेन्ट, नागल हटनाला, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248001 से प्रकाशित।

सम्पादक:
गार्गी मिश्रा
8765441328

समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे।